



सामाजिक रूप से सचेत व्यवहार

भारत 50 फीसदी पर है। उल्लेखनीय है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ सॉरी-थैंक्यू कहना नहीं है। वरना दुनिया के सबसे विनम्र लोगों वाला देश कनाडा इस स्टडी में 57 फीसदी पाइंट के साथ कम स्कोर वाले देशों में शामिल नहीं होता।

ममता सिंह।

अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नैशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट ने बहुतों का ध्यान खींचा। इस स्टडी में पहली बार अलग-अलग देशों के संदर्भ में यह देखने की कोशिश हुई कि सामाजिक रूप से सचेत व्यवहार करने के मामले में किस देश के लोग कहां खड़े हैं? सामाजिक रूप से सचेत व्यवहार से मतलब है उन लोगों के हितों का, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना, जो सीधे तौर पर हमसे जुड़े नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं। खास बात यह कि इसमें सिर्फ उन व्यवहारों को शामिल किया गया, जिनके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करता पड़ता या जिनमें समय लगाने की जरूरत नहीं

होती। 31 देशों के लोगों पर की गई इस स्टडी के मुताबिक, भारत इस मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर है। तुर्की और इंडोनेशिया ही उससे नीचे हैं। इस मामले में टॉप पर है जापान, जहां लोगों के अच्छे व्यवहार का प्रतिशत 72 है। ऑस्ट्रेलियाई 69 फीसदी और मेक्सिकन 68 फीसदी के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर हैं। भारत 50 फीसदी पर है। उल्लेखनीय है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ सॉरी-थैंक्यू कहना नहीं है। वरना दुनिया के सबसे विनम्र लोगों वाला देश कनाडा इस स्टडी में 57 फीसदी पाइंट के साथ कम स्कोर वाले देशों में शामिल नहीं होता। बहरहाल, यह नंबरिंग खास मायने नहीं



रखती। महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि आम तौर पर हमारा व्यवहार हमारी व्यापक सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है, जो काफी हद तक हमारे सांस्कृतिक परिवेश से तय होती है। विभिन्न देश, समाज इस मामले में अलग-अलग स्थिति में क्यों हैं, यह एक जटिल सवाल है। इस स्टडी रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि विभिन्न देशों की अलग-अलग स्थिति की व्याख्या करने के लिए और अध्यायन करने की जरूरत है, लेकिन दो बातें साफ हैं। एक तो यह कि जिन देशों और समाजों में लोग उन्नत सामाजिक चेतना से लैस हैं यानी जहां वे अनजान लोगों के हितों, उनकी भावनाओं को लेकर भी सचेत होते हैं, वहां पारस्परिक विश्वास ज्यादा होता है जिसका सकारात्मक प्रभाव

राजनीतिक, आर्थिक नीतियों और विकास पर होता है। उदाहरण के लिए, वहां कड़े कानूनों की जरूरत नहीं पड़ती और माहौल में खुलापन होता है।

दूसरी बात यह है कि ये सामाजिक मानदंड एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ इनमें बदलाव आता है। मतलब यह कि चाहे जितनी भी जटिल प्रक्रिया हो, उसका सावधानी से विश्लेषण करते हुए बदलाव की इस प्रक्रिया को सकारात्मक मोड़ दिया जा सकता है। अगर अपने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में इसकी पड़ताल की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी को परिवार मानने के आदर्श के साथ अपने ही समाज के कुछ खास हिस्सों को खुद से अलग मानने के यथार्थ का विरोधाभास अच्छी केस स्टडी हो सकता है।

जोर से प्रहार

अशोक बोहरा।
नन्हीं चींटियों पर
सर्प की धौंस
का कोई असर
नहीं पड़ा। यह
देखकर सर्प का
गुस्सा बहुत
अधिक बढ़ गया
और उसने
अपनी पूंछ से
बिल पर कोड़े

धर्म-दर्शन



की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत गुस्सा आया। क्षण भर में हजारों चींटियां बिल से निकलकर बाहर आईं और सर्प के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगीं। नागराज का लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह असहाय वेदना से बिलबिला उठे। असंख्य चींटियां उसे नोच-नोचकर खाने लगीं। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। उसके बाद भी चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसका नर्म मांस नोच-नोचकर खा गईं।

संपादकीय

विपक्ष को मौका

महंगाई को सियासत के केंद्र बिंदु में लाने के लिए विपक्ष को मौका ही मौका दिख रहा है। कांग्रेस ने 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच महंगाई के विरोध में पूरे देश में जन आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सामने सरकार को घेरने का बड़ा मौका होगा। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने एनबीटी से कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए सबसे कॉमन मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब विपक्षी दल आपस में ही भिड़ रहे हैं, उन्हें किसान आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए जो तमाम मतभेद भुलाकर चुनावी जंग में सभी दलों को सरकार के खिलाफ एक होने का सियासी अवसर देते हैं। पिछले कुछ सालों से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मिश्रण से बने मुद्दे को बीजेपी ने ऐसा कवच बनाया है जिसे भेदने का नुस्खा विपक्ष अब तक तलाश नहीं पाया। बीजेपी ने इन मुद्दों को सामने रखकर पूरी राजनीति को ही बदल दिया। अब विपक्ष पूरी ताकत से मुद्दों को अपने पिच पर लाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे को मुख्यधारा में लाने की कोशिश में है। लगातार बढ़ती कीमत ने उसे एक सियासी प्लेटफॉर्म दे दिया है। जाहिर है, अगले कुछ महीने इस मोर्चे पर सरकार का डैमेज कंट्रोल प्रयास और विपक्ष का वार देखने को मिलता रहेगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम इस दिशा में एक संकेत भी देंगे कि आम लोग किस के पक्ष को सही मान रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल-गैस के अलावा सरसों तेल और आम लोगों के सरोकार से जुड़ी दूसरी चीजें भी महंगी हुईं। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अगले महीने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली है।

सरकार क्यों है पशोपेश में

नरेंद्र नाथ।

पूरे देश में अभी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के सात साल के ऊपर के समय में पहली बार महंगाई के मोर्चे पर न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि आम लोगों के भी कड़े सवाल का सामना कर रही है। कोविड के कारण सुस्त हुए आर्थिक हालात के बीच महंगाई आम लोगों के लिए डबल झटके के रूप में सामने आई। पेट्रोल-डीजल-गैस के अलावा सरसों तेल और आम लोगों के सरोकार से जुड़ी दूसरी चीजें भी महंगी हुईं। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अगले महीने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली है।

ऐसी चर्चा भी उठी कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की कटौती कर आम लोगों को राहत दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा करने के संकेत नहीं दिए। हालांकि सरकार ने इतना जरूर कहा कि वह अगले कुछ दिनों में कीमत कम करने की दिशा में कदम उठा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं के बीच कहीं संतुलन बनाने की कोशिश में है। मतलब महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण भी रहे और दूसरी ओर सरकार के पास कल्याणकारी



योजनाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध रहे। लेकिन इस बार यह संतुलन साध पाना उतना आसान नहीं लगता।

बढ़ती कीमतों के बाद भी अब तक इस मोर्चे पर सरकार का कोई बड़ा कदम न उठाना लोगों को परेशानी में डालने वाला है। मगर सरकार के सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं है। ऐसे में सरकार ऐसे संतुलन की तलाश में है जिससे उसके सारे समीकरण दुरुस्त रहें। सरकार की प्राथमिकता कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जिनकी बढ़तीत उसे अब तक बड़ा सियासी प्रीमियम मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुआई में बीजेपी इनमें भी किसी तरह की कटौती नहीं कर सकती है। ऐसी भी खबरें आईं कि सरकार किसान सम्मान निधि के लिए राशि बढ़ा सकती है। दरअसल 2019 आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र

सरकार ने किसान सम्मान निधि का ऐलान किया। इसके तहत सभी किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना पर सालाना 75 हजार करोड़ खर्च आता है। खबरों के मुताबिक आम चुनाव से पहले इस निधि की राशि बढ़ सकती है। इसके अलावा उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले आक्रामक रूप से लॉन्च कर सकती है। इसके लिए सरकार को पर्याप्त धनराशि की जरूरत होगी। कोविड के कारण लगभग डेढ़ साल सरकार की कमाई प्रभावित रही। सरकार का खजाना पहले से ही कोविड से निपटने में खाली हुआ।

इन हालात में सरकारी के पास बेहद सीमित विकल्प हैं। वह मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स या दूसरा बोझ नहीं डाल सकती है। उनके लिए भी महंगाई बड़ा मुद्दा है लेकिन इसे कम करने की एवज में सरकार उन पर दूसरा बोझ नहीं बढ़ा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर वह दबाव में एक्साइज में कटौती करती है तो आगे उसे निवेश में कटौती करनी होगी जो कि चुनावी साल में जोखिम भरा होगा। और टैक्स में कमी नहीं करती है तो आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हाल में आए तमाम ओपिनियन पोल में कहा गया कि महंगाई अब लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बन रही है।

यूडीएफ बजट-5407				* * * * *			
6	9	7	4	8			
8	5	6	2	4	9		
7				6	3		
3	9	5		1			
1		8				5	
6			2	9	3		
4	7					2	
8	2		5	9	1	7	
1		2	3			5	8

अपना ब्लॉग

तीसरी लहर आ गई तो दांव उल्टा पड़ सकता है। सरकार उम्मीद कर रही है कि अगले कुछ महीने में विश्व में कच्चे माल की कीमत स्थिर होगी और कीमतें खुद नियंत्रण में आएंगी। लेकिन उसे पता है कि अगर लंबे समय तक कीमत बढ़ी रह गई तो उसके अपने सियासी नुकसान हैं। दरअसल मोदी सरकार को अपने पहले टर्म में आर्थिक मामलों पर खासकर महंगाई के मोर्चे पर अधिक सवालों का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि नोटबंदी से इकॉनमी जरूर प्रभावित हुई लेकिन लोगों ने तब उसे पीएम नरेंद्र मोदी का बोल्ट प्रयोग मानकर उन्हें पूरे अंक दिए। लेकिन इस बार यहां भी हालात जुदा है और विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा। इन सबके बीच बेरोजगारी का मसला भी सामने आ रहा है। इसे लेकर सरकार की दुविधा यह है कि अगर अभी राहत के उपाय उठा दें और कोविड की तीसरी लहर आ गई तो दांव उल्टा पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों विश्व के कई देशों में कोविड फिर पसरता दिख रहा है जिस कारण वहां लॉकडाउन जैसे कदम भी उठाने पड़े हैं।

